मंथन



राजवीर जाट

अर्थशास्त्री

कृषि संकट और रोजगार सृजन

देश की लगभग आधी जनसंख्या खेती से जुड़े कार्यों में रोजगार पाती है, जबकि जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत बहुत कम है। बेहतर रणनीति बनाते हुए इसे बदला जा सकता है

देश के कई इलाके इस समय सूखे की मार झेल रहे हैं। हर सूखे के साथ वही बहस लौट आती है- कर्जमाफी, मुआवजा और यह सलाह कि देश को खेती पर निर्भरता घटानी चाहिए। लेकिन यह सही समय है कि हम ग्रामीण विकास की रणनीति पर नए सिरे से सोचें और पूछें कि किसान परिवारों के पास असल में किस चीज की कमी है। आम धारणा है कि खेती कम उत्पादकता वाला क्षेत्र है। देश के लगभग 45 प्रतिशत कामगार खेती में हैं, लेकिन जीडीपी में खेती का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत ही है। इससे लगता है कि खेती से बाहर काम करने वाला व्यक्ति कई गुना ज्यादा उत्पादक है, और समाधान यही है कि लोगों को खेती से बाहर निकाला जाए।

जर्नल आफ डेवलपमेंट इकोनमिक्स में प्रकाशित एक हालिया शोध से पता चलता है कि यह तस्वीर धुंधली है। गैर-कृषि क्षेत्र एक जैसा नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा असंगठित है, यानी छोटे उद्यम- छोटी दुकानें, निर्माण मजदूर, छोटी वर्कशाप और स्वरोजगार। इसके मुकाबले संगठित क्षेत्र में बड़े उद्यम आते हैं। राष्ट्रीय आंकड़ों के आधार पर जब हम कामगारों की शिक्षा, साल में काम के घंटों और उत्पादन में श्रम के हिस्से का अंतर ध्यान में रखते हैं, तो खेती और असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के बीच उत्पादकता का अंतर लगभग खत्म हो जाता है। वर्ष 2022-23 में असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र खेती से केवल 1.08 गुना उत्पादक था, जबकि संगठित क्षेत्र लगभग 1.8 गुना। जिन उद्योगों में 76 प्रतिशत से ज्यादा कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं, वहां खेती के मुकाबले कोई खास अंतर नहीं मिलता। गैर-कृषि क्षेत्र के 63 से 75 प्रतिशत कामगार ऐसे ही उद्योगों में हैं।

कुछ गैर-कृषि कामों में तो यह अनुपात एक से भी कम है। यानी उतनी ही पढ़ाई वाला व्यक्ति, उतने ही घंटे काम करके, वहां खेती से भी कम उत्पादन करता है। दुर्भाग्य से खेतिहर मजदूर सबसे आसानी से इन्हीं कार्यों में जा पाते हैं। कई लोगों के लिए "खेती छोड़ने" का मतलब एक कम उत्पादक काम से दूसरे कम उत्पादक काम में जाना है। उसकी आमदनी इसलिए कम है, क्योंकि मौसमी खेती में साल भर काम नहीं मिलता। हमारे शोध में असंगठित क्षेत्र के मुकाबले उत्पादकता के अंतर का सबसे बड़ा कारण यही है- काम के घंटों का अंतर। नीति के तीन हिस्से होने चाहिए- इस पीढ़ी के लिए ज्यादा कार्य-दिवस, अगली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा और असंगठित क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने वाला सुधार।

पहला, वयस्क किसान और मजदूर के लिए सबसे व्यावहारिक समाधान साल भर काम है। सूखे में ग्रामीण रोजगार के काम जल्द और बड़े पैमाने पर शुरू हों, खासकर तालाब, जल-संरक्षण और चारा बैंक जैसे काम। खाली मौसम में बाहर काम करने जाने वाले परिवारों को राशन और स्वास्थ्य लाभ के लिए दोनों स्थान का विकल्प मिलना चाहिए। ब्लाक और जिला अधिकारियों की पदोन्नति इस बात से जुड़ी हो कि उन्होंने वास्तव में कितने कार्य-दिवस दिलाए और सामाजिक आडिट के नतीजे कैसे रहे, तभी ये सुधार टिकाऊ होंगे। पशुपालन जैसे सहायक व्यवसाय खेत खाली होने पर भी रोज की आमदनी देते हैं। इनके लिए सब्सिडी के साथ गांव के स्तर पर खरीद और बैंक की मजबूत व्यवस्था चाहिए। अमूल जैसी सहकारी समितियों ने दिखाया है कि गांव में ही उचित दाम पर रोज खरीद की गारंटी लाखों परिवारों की आमदनी बदल सकती है। ग्रामीण पर्यटन भी एक नया रास्ता है। शहरों के कई लोग गांव में कुछ दिन रहना चाहते हैं, पर परिवहन, सुरक्षा और ठहरने को लेकर भरोसा नहीं होता। निजी कंपनियां होमस्टे चला सकती हैं, सरकार मानक व सुरक्षा का कवच दे सकती है।



खेती पर आधारित छोटे उद्यमों से किसान को जोड़ने से उनकी आय बढ़ सकती है। प्रतीकात्मक

दूसरा, अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दें। हमारे शोध में उत्पादकता के अंतर का दूसरा बड़ा कारण शिक्षा है और संगठित क्षेत्र की ऊंची उत्पादकता वाली नौकरियों तक पहुंचने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। तीसरा, छोटे उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाएं। खेती से बाहर जाने वाले ज्यादातर कामगार छोटे, असंगठित कारोबारों में ही जाएंगे, और जब तक इनकी उत्पादकता नहीं बढ़ती, खेती छोड़ने से आमदनी नहीं बढ़ेगी। आसान कर्ज, डिजिटल भुगतान, बाजार तक पहुंच, पंजीकरण व विस्तार के सरल नियम और सूखे इलाकों के छोटे शहरों में औद्योगिक क्लस्टर व अप्रेंटिसशिप छोटे कारोबारों को बढ़ाकर संगठित क्षेत्र की इकाइयों में बदल सकते हैं। असली खाई खेती और गैर-खेती के बीच नहीं, बल्कि असंगठित व संगठित क्षेत्र के बीच है, व इसे पाटना ही समाधान है।

कर्जमाफी और मुआवजा संकट में जरूरी राहत हैं, लेकिन ये ग्रामीण विकास की रणनीति नहीं हैं। समस्या किसान में नहीं, उसके पास विकल्पों की कमी में है। वर्तमान पीढ़ी के लिए ज्यादा कार्य-दिवस, अगली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा और घर के पास ज्यादा उत्पादक काम, यही नई रणनीति का आधार होना चाहिए। तभी ग्रामीण आजीविका से जुड़े विकल्पों में व्यापक वृद्धि हो सकती है।